



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 / 08 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 27 अगस्त, 2024

संख्या वि०स०—विधायन— विधेयक / 1-68 / 2024.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 115—राजपत्र / 2024—30—08—2024 (5305)

2024 जो आज दिनांक 27 फरवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2024 का विधेयक संख्यांक 4

बाल—विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।
4. धारा 18—क का अंतःस्थापन।
5. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 4

बाल—विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल—विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल—विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (15 of 1872) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936; (3 of 1936) मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 (26 of 1937) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (43 of 1954) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (25 of 1955) या विवाह के संबंध में अपनाई जा रही किसी विधि या प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के प्रतिकूल या उसके असंगत होते हुए भी यह हिमाचल प्रदेश के राज्य क्षेत्र में अधिवासित सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

(3) इस अधिनियम की यह धारा, धारा 2 के खण्ड (ii) और धारा 4 तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगी और शेष उपबन्ध उनके अधिनियमन की तारीख से दो वर्ष के समापन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के संबंध में ऐसे किसी उपबन्ध में किसी संदर्भ का अर्थ उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के संदर्भ में लगाया जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन.—बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) “बालक” से, ऐसा पुरुष या नारी अभिप्रेत है, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;”

(ii) खण्ड (ख) में “दोनों पक्षकारों में से” शब्दों के पश्चात् “,पक्षकारों को शासित करने वाली किसी प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल या असंगत होते हुए भी,” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 3 का संशोधन.—“मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) में,— “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 18-क का अंतःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 18-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“18-क. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.—इस अधिनियम के उपबन्धों का, पक्षकारों को शासित करने वाली किसी प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल या असंगत होते हुए भी प्रभाव होगा।”

5. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उनमें वर्णित रीति में संशोधन किया जाएगा।

अनुसूची (धारा 5 देखें)

क्रम संख्या	वर्ष	अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1872	15	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872.	धारा 60 के खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:— “(1) विवाह का आशय रखने वाले पुरुष और स्त्री की आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी;”
2.	1936	3	पारसी विवाह और विच्छेद-अधिनियम, 1936.	(क) धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में “वह महिला है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है” शब्दों के स्थान पर “वह महिला है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है” शब्द रखे जाएंगे। (ख) द्वितीय अनुसूची में, “यदि विवाह के पक्षकार 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके पिता या संरक्षक के

				हस्ताक्षर" पद का लोप किया जाएगा।
3.	1954	43	विशेष विवाह अधिनियम, 1954.	धारा 4 के खण्ड (ग) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
4.	1955	25	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955.	(क) धारा 5 के खण्ड (iii) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे। (ख) धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (iv) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह अनुष्ठान सम्पन्न कराने और तत्संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों को प्रतिषिद्ध करने के लिए उपबन्धित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। आधुनिक युग में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। तथापि, बाल विवाह न केवल उनके व्यवसाय की प्रगति में बल्कि उनके शारीरिक विकास में भी बाधक है। लैंगिक समानता और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों के लिए उपबन्ध करने हेतु बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन किया जाना तथा बालिकाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(डॉ० (कर्नल) धनी राम शांडिल)
प्रभारी मंत्री।

शिमला:

तारीख:, 2024

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(डॉ० (कर्नल) धनी राम शांडिल)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख:, 2024

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 4 OF 2024

**THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH
AMENDMENT) BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title, application and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Insertion of section 18A.
5. Amendment of certain enactments.

BILL No. 4 OF 2024

**THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH
AMENDMENT) BILL, 2024**

(As INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, application and commencement .—(1) This Act may be called the Prohibition of Child Marriage (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2024.

(2) It shall apply to all persons domiciled in the territory of the State of Himachal Pradesh notwithstanding anything contrary or inconsistent therewith contained in the Indian Christian Marriage Act, 1872 (15 of 1872) the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (3 of 1936) the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 (26 of 1937) the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954) the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) or any other law or custom or usage or practice in relation to marriage, under any other law for the time being in force.

(3) This section, clause (ii) of section 2 and section 4 shall come into force immediately and the remaining provisions shall come into force on the date of completion of two years from the date of its enactment and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (hereinafter referred to as the “principal Act”),—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) “child” means a male or female who has not completed twenty-one years of age;” and

(ii) in clause (b), after the words “is a child”, the words “notwithstanding anything to the contrary or inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, including any custom or usage or practice governing the parties” shall be inserted.

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principle Act, in sub-section (3), for the words “two years”, the words “five years” shall be substituted.

4. Insertion of section 18-A.—After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“18A. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything contrary or inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, including any custom or usage or practice governing the parties.”.

5. Amendment of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE shall be amended in the manner mentioned therein.

THE SCHEDULE

(See section 5)

Sl. No.	Year	Act No.	Short title	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1872	15	The Indian Christian Marriage Act, 1872.	In section 60, for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:— “(1) the age of the man and woman intending to be married shall not be under twenty-one years;”.
2.	1936	3	The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936	(a) in section 3, in sub-section (1), in clause (c), for the words “female, has not completed eighteen years of age”, the words “female, has not completed twenty-one years of age” shall be substituted. (b) in Schedule II, the expression “Signatures of the fathers or guardians of the contracting parties under 21 years of age” shall be omitted.
3.	1954	43	The Special Marriage Act, 1954	In section 4, in clause (c), for the words “eighteen years”, the words “twenty-one years” shall be substituted.
4.	1955	25	The Hindu Marriage Act, 1955	(a) in section 5, in clause (iii), for the words “eighteen years”, the words “twenty-one years” shall be substituted. (b) in section 13, in sub-section (2), in clause (iv), for the words “eighteen years”, the words “twenty-one years” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 was enacted to provide for the prohibition of solemnisation of child marriages and for matters connected therewith or incidental thereto. In today's world the women are progressing in every field. The early marriages, however, act as a hindrance not only in the progress of their career but also in their physical development. In order to provide for gender equality and opportunities of obtaining higher education, it has become necessary to increase the minimum age of marriage for the girls. Thus, it is proposed to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 and other related Acts in their application to the State of Himachal Pradesh and increase the minimum age for marriage for girls to 21 years.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(DR. (COL.) DHANI RAM SHANDIL)

Minister-in-charge.

SHIMLA:

The.....2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

— Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

— Nil—

**THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)
BILL, 2024**

A

BILL

to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007) in its application to the State of Himachal Pradesh.

(DR. (COL.) DHANI RAM SHANDIL)

Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

SHIMLA:

The....., 2024

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th July, 2024

No. HFW-B-B/8/2021.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of Department of Cardiology at Dr. RKGMC, Hamirpur alongwith creation of the following posts in the concerned department in the public interest with immediate effect:—

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts
1.	Professor	01
2.	Assistant Professor	01
3.	Senior Resident	01

The faculty posts shall be filled up on regular basis in accordance with the provisions of the R&P Rules. The tenure post Senior Resident shall be filled up as per the provisions of the Resident Doctor Policy notified on dated 24-12-2021.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* its UO No.56105219-Fin-F-(B)-1-10/2019, dated 12-07-2024.

By order,

Sd/-
Secretary (Health).

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th, August, 2024

eFile No. 226033 (Year-2024).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create the following 28 posts of Medical Officers (Specialist) for IGMC Shimla and Medical Officers (Superspecialist) for Atal Institute of Medical Super Specialties (AIMSS) at Chamiana, Shimla, in the public interest, with immediate effect, as under:—

1. FOR IGMC, Shimla:—

Sl. No.	Name of Specialty/ Department	Number of Post(s)
1.	General Medicine	10
2.	Orthopaedics	02
3.	Dermatology	01
4.	Casualty/ Emergency Medicine	02
5.	Ophthalmology	02
6.	ENT	01
7.	Paediatrics	03
Total ..		21

2. FOR AIMSS Chamiana (Shimla):—

Sl. No.	Name of Specialty/ Department	Number of Post(s)
1.	Urology	01
2.	Cardiology	01
3.	Nephrology	01
4.	Neurology	01
5.	Neurosurgery	01
6.	Endocrinology	01
7.	Gastroenterology	01
Total ..		07

The above newly created posts shall be filled up strictly as per the terms and conditions annexed at **Annexure-A**.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the additional manpower *i.e.* Staff Nurse, Operation Theatre Assistant (OTA) Nursing Orderly-*cum*-Dresser, Dietician, Physiotherapist, Data Entry Operator-*cum*-Multi Task Operator etc. will be hired on outsource basis through authorised service providers, after completion of all codal formalities in this regard well in advance.

This issues with the prior approval of Finance Department obtained *vide* their U.O. No.: 56118816-Fin-F(B)1-11/2021-II, dated 07-08-2024.

By order,

M. SUDHA DEVI,
Secretary (Health).

Annexure-A

The terms and conditions for selection as well as termination of services in respect of Medical Officer (Specialist) and Medical Officer (Superspecialist) in Government Medical Colleges/ Institution of the State

1. The Principal concerned shall advertise the posts after obtaining the approval of the Government for filling up of the posts and constitute a Selection Committee who will examine the relevant documents *i.e.* academic certificates and teaching experiences etc. of the applicants.
2. After scrutinizing the relevant documents by the concerned Selection Committee, the ratio of 1:3 candidates will be called for walk-in-interview by the Principal concerned.

3. The preference shall be given to the Superspecialist doctors *i.e.* DM/ M.Ch. course and or DNB Superspecialty course strictly on the basis of norms as well as qualification fixed by the National Medical Commission. In case, the qualified Superspecialists are not available for any specialty/Superspecialties as per the NMC norms, then the candidate will be selected on the basis of qualifications fixed by the PGIMER or AIIMS OR Medical specialists *i.e.* PG (MD/MS) in the related category. The advertisement shall be done separately for those Superspecialties are not available.

In case, the eligibility of any candidate is not being finalized by the Selection Committee, the Principal concerned shall refer the proposal to the Director, Medical Education who will further place the matter before 'Screening Committee who will examine the eligibility' constituted by the Government from time to time and on the basis of the recommendations of the said Committee, the Principal concerned shall take further necessary action accordingly.

4. At the time of joining, the candidate will submit a '**legal undertaking in the form of affidavit**' that he/she shall not claim for regularization/ continuation/ promotion and any other ancillary benefits against the post he/she engaged. The candidate shall be purely on temporary basis and shall not confer any right of regularization/ continuation/ promotion and any other ancillary benefits.
5. The candidate shall not claim to increase his/her monthly emoluments/ allowances/ pay on the analogy of other regular Government employees of the Medical Education/ Health Department of Himachal Pradesh.
6. The Medical Officer (Specialist) OR Medical Officer (Superspecialist) shall be engaged initially for a period of three years and his/ her period may be extended by the Government on the recommendations of the Principal concerned. However, the candidate shall not claim that his/her services may be continued. In all case, further extension can be granted on the recommendations of the Principal concerned as well as keeping in view of the larger public interest of patient care and the Government will be competent authority for the same.
7. If the Government does not grant timely extension despite the recommendations of the concerned Principal, the services of the candidate will automatically terminate from the next day after the completion of his/her normal tenure.
8. The candidate/ selectee will be governed in accordance with the terms and conditions fixed by the Government from time to time. The rules, regulations and orders in force from time to time as applicable to other Government servants such as CCS (CCA) Rules and CCS (Conduct) Rules, instructions/ guidelines/ notifications issued by the Department of Personnel/ Finance, Government of Himachal Pradesh shall not be applicable to the selectee.
9. On being offered appointment on tenure basis, the selectee shall sign an agreement as per the terms and conditions fixed by the Government from time to time and submit joining report to the Government through Principal concerned.
10. The services of the selectee are liable to be terminated by the Government in case the work and conduct/ performance of the candidate during the tenure period is not found satisfactory.
11. During the tenure period, no advance will be given to the selectee.

12. The selectee will be entitled for one day Casual Leave after putting in one month services without any interruption. However, the selectee will also be entitled for 180 days Maternity Leave under the Maternity Benefits Act, 1961 and 10 days Medical Leave. However, he/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the selectee:

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar year.

13. Unauthorized/ wilful absence from the duty without approval of the controlling authority *i.e.* Principal concerned, shall automatically lead to the termination of the services. During the period of unauthorized absence from the duty, the emoluments shall not be paid for the said period to the selectee.
14. The transfer of the candidate/selectee shall not be permitted from one Govt. Medical College/ institution to another in any circumstances.
15. The selectee will have to submit a certificate of his/her fitness from the Medical Board of the concerned district. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness.
16. The selectee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to other regular Government employee *i.e.* Medical Officer.
17. The appointment is provisional and is subject to the educational qualification and other certificates being verified by the Principal concerned through proper channel and if the verification reveals that the same is/are false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
18. He/she will have to give a declaration to the effect that he/she has only one living spouse, if married.
19. He/she will have to take an oath of allegiance/ faithfulness to the Constitution of India or marking a solemn affirmation.
20. He/she will have to produce all the certificates of the requisite qualifications to the concerned post in original at the time of joining.
21. The Principal concerned shall be competent authority under these terms and conditions to ensure that the agreement has been signed strictly as per the terms and conditions filed by the Government for the post of Medical Officer (Specialist) and Medical Officer (Superspecialist) and the Director Medical Education & Research, Himachal Pradesh shall competent authority to sign the agreement.
22. The benefit of Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ CPF/ GPF etc. will not be applicable to the appointee.
23. The Government may increase and decrease the monthly emoluments/ salary of the above Medical Officers (Specialist) and Medical Officers (Superspecialist) keeping in view of the State exchequer.

24. The Principal concerned shall be competent authority to ensure that the legal undertaking in the form of affidavit is submitted by the concerned/selected candidate before their joining. The submission of legal undertaking/ affidavit is required to be mentioned in the appointment orders of the selected candidate after obtaining the approval of the Government:

Provided that the Principal concerned shall be competent authority to ensure that the selectee has submitted correct affidavit as per the terms and conditions fixed by the Government from time to time.

25. The monthly emoluments/ salary of the Medical Officer (Specialist) and Medical Officer (Superspecialist) will be fixed as under:—

Sl.No.	Name of post	Fixed Monthly Salary/ Emoluments
1.	Medical Officer (Specialist)	Rs. 75,000/-
2.	Medical Officer (Superspecialist)	Rs. 120,000/-

26. Contract agreement in the legal form which will be applicable for the above appointment on tenure basis, will be as per **Annexure-B**.

Annexure-B

CONTRACT AGREEMENT

Form of contract/ agreement to be executed between the (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this day of in the year between Sh./Smt.....s/o or d/o Sh. Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through (hereinafter to be referred as SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Medical Officer (Specialist) and Medical Officer (Superspecialist) on contract basis through walk-in-interview on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an (designation) for the period of 03 years commencing on the day of and ending on the day of Further, the same may be

extendable on year to year basis. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* onand information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/ renewal of contract period, the Head of Department of respective specialty/ Principal concerned shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The FIRST PARTY shall not claim to increase his/her monthly emoluments/ allowances/ pay on the analogy of other regular Government employees working under the SECOND PARTY.
3. The FIRST PARTY shall be engaged initially for a period of _____ year and his/ her period may be further extended by the Government on the recommendations of the Principal concerned. However, the FIRST PARTY shall not claim that his/ her services may be continued. In all case, further extension can be granted on the recommendations of the Principal concerned as well as keeping in view of the larger public interest of patient care and the SECOND PARTY will be competent authority for the same.
4. The FIRST PARTY at the time of joining shall submit a separate '**legal undertaking in the form of affidavit**' to the effect that he/she has been engaged purely on temporary basis and shall not confer any right of regularization/ continuation/ promotion/ extension and any other ancillary benefits against the post he/she is engaged and accept the offer of appointment as well as the terms & conditions fixed by the Government from time to time.
5. If the SECOND PARTY does not grant timely extension despite the recommendations of the concerned Principal, the services of the FIRST PARTY will automatically terminate from the next day after the completion of his/her normal tenure.
6. The FIRST PARTY will be governed in accordance with the terms and conditions fixed by the SECOND PARTY from time to time. The rules, regulations and orders in force from time to time as applicable to other Government servants such as CCS (CCA) Rules and CCS (Conduct) Rules, instructions/ guidelines/ notifications issued by the Department of Personnel/ Finance shall not be applicable upon the FIRST PARTY.
7. On being offered appointment on tenure basis, the FIRST PARTY shall sign an agreement as per the terms and conditions fixed by the SECOND PARTY from time to time and submit joining report to the Government through Principal concerned.
8. The services of the FIRST PARTY are liable to be terminated by the SECOND PARTY in case, the work and conduct/ performance during the tenure period is not found satisfactory.
9. During the tenure period, no advance will be given to the FIRST PARTY.
10. The FIRST PARTY will be entitled for one-day Casual Leave after putting in one month services without any interruption. However, the FIRST PARTY will also be entitled for 180 days Maternity Leave under the Maternity Benefits Act, 1961 and 10 days Medical Leave. However, FIRST PARTY shall not entitle for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the FIRST PARTY:

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar year.

11. Unauthorized/ wilful absence of the FIRST PARTY from the duty without approval of the controlling authority *i.e.* Principal concerned, shall automatically lead to the termination of the services. During the period of unauthorized absence from the duty, the emoluments shall not be paid for the said period to the FIRST PARTY.
12. The transfer of the FIRST PARTY shall not be permitted from one Government Medical College/ institution to another institution/ Medical Colleges in any circumstances.
13. The FIRST PARTY will have to submit a certificate of his/her fitness from the Medical Board of the concerned district. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness.
14. The FIRST PARTY will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to other regular Government employee *i.e.* Medical Officer.
15. The appointment of the FIRST PARTY is provisional and is subject to the educational qualification and other certificates being verified by the Principal concerned through proper channel and if the verification reveals that the same is/are false, the services of the FIRST PARTY will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
16. The FIRST PARTY will have to give a declaration to the effect that he/she has only one living spouse, if married.
17. The FIRST PARTY will have to take an oath of allegiance/ faithfulness to the Constitution of India or marking a solemn affirmation.
18. The FIRST PARTY will have to produce all the certificates of the requisite qualifications to the concerned post in original at the time of joining.
19. The benefit of Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ CPF/ GPF etc. will not be applicable to the FIRST PARTY.
20. The SECOND PARTY shall be competent authority to increase and decrease the monthly emoluments/ salary of the FIRST PARTY keeping in view of the State exchequer.
21. The monthly emoluments/ salary of the SECOND PARTY shall be fixed @ Rs. _____.

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

The details of the FIRST PARTY are as under:

NAME: _____

s/o, d/o, w/o: _____

RESIDING AT (Permanent Address):

Correspondence Address:

MOBILE No: _____

E-mail address: _____

AADHAR No.: _____

In the Presence of Witness:—

1. Name : _____

Father's Name: _____

Full Address: _____

Signature of the FIRST PARTY

2. Name : _____

Father's Name: _____

Full Address: _____

In the Presence of Witness:—

1. Name : _____

Father's Name: _____

Full Address: _____

Signature of the SECOND PARTY

2. Name : _____

Father's Name: _____

Full Address: _____

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th March, 2024

No. LEP-A004/5/2023.—In supersession to this department's Notification No. LEP-A004/5/2023, dated 1st February, 2024 and in exercise of the powers conferred under section 18(3) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, and Rule 251(2) of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules—2008, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Nardev Singh Kanwar, Village-Luthan, P.O. Sudhangal, Tehsil-Jwalamukhi, District-Kangra (H.P.) as the Chairman of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers' Welfare Board with immediate effect.

By order,

DR. ABHISHEK JAIN,
Secretary (Lab.& Emp.)

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th August, 2024

File No. 5-1/71-DP-Appptt.(2024).—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the transfer of Ms. Nandita Gupta, IAS (HP:2001) Advisor (Coordination), Government of Himachal Pradesh, New Delhi and to appoint her as Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh, Shimla, with immediate effect, in the public interest, with the prior approval of the Election Commission of India.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order that Ms. Nandita Gupta, IAS (HP:2001) shall also function as Secretary (Election) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.

The Notification No. 154/HP/2024-P.Admn, dated 27-08-2024 (English & Hindi version) of the Election Commission of India is also attached to be published in the next Gazette of Himachal Pradesh Government for general information.

By order,

Sd/-
(PRABODH SAXENA),
Chief Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 27 अगस्त, 2024

05 भाद्रपद, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 154/HP/2024-P.Admn.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री मनीष गर्ग, आई.ए.एस. के स्थान पर सुश्री नंदिता गुप्ता, आई.ए.एस. (एच. पी.-2001) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. सुश्री नंदिता गुप्ता, आई.ए.एस., हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थी।

3. सुश्री नंदिता गुप्ता, आई.ए.एस., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

आदेश से,
(राहुल शर्मा)
प्रधान सचिव

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi 110001.

Dated: 27th August, 2024
05 Bhadra, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/HP/2024-P.Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Himachal Pradesh hereby designates Ms. Nandita Gupta, IAS, (HP:2001) as the Chief Electoral Officer for the State of Himachal Pradesh with effect from the date she takes over charge and until further orders in place of Shri Maneesh Garg, IAS.

2. Ms. Nandita Gupta, IAS, cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Himachal Pradesh, which she may be holding before such assumption of office.

3. Ms. Nandita Gupta, IAS while functioning as the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Himachal Pradesh except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By order,

Sd/-
(RAHUL SHARMA),
Principal Secretary.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री शम्भू राम पुत्र हरी सिंह पुत्र भगत राम, निवासी सरसकान, डा0 बरोटी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम
आम जनता

दरखास्त बराये नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री शम्भू राम पुत्र हरी सिंह पुत्र भगत राम, निवासी सरसकान, डा0 बरोटी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण पत्र स्थानीय पंजियक/नकल जमाबन्दी महाल लौगणी प्रस्तुत किया है कि उसका नाम महाल सरसकान में शम्भू दर्ज है जो कि गलत है राजस्व के रिकार्ड में सही नाम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सही नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन पेशी दिनांक 20-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा नाम दर्ज करके ओदश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रूप लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी पांगणा, उप-तहसील पांगणा,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 13/24

तारीख मरजुआ :01-07-2024

तारीख पेशी :10-09-2024

मुशत्री मुनादी

तिलक राज पुत्र श्री देवीराम, निवासी ब्याडी महाल कनेरी/223, डा0 मरोठी, उप-तहसील पांगणा,
जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

घेलू पुत्र धर्मू, निवासी दोहडू महाल कनेरी/223, डा0 मरोठी, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0। आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम खाता खतौनी नं0 19/22, खसरा कित्ता-10, रकबा तादादी 14-03-06, बीघा वाक्या मुहाल कनेरी/223, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

तलवी:-

1. देवकू पत्नी मादू, निवासी महाल कनेरी, डा0 मरोठी, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 2. रेशमू पत्नी दलू, निवासी महाल कनेरी, डा0 मरोठी, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0, 3. लीला देवी पुत्री श्रीमती सन्ती, निवासी महाल कनेरी, डा0 मरोठी, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0

यह प्रार्थना पत्र बाबत तकसीम प्रार्थीगण ने स्वयं न्यायालय में पेश किया है। उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखा है कि प्रार्थी का फरीकदोम के साथ खाता मुशत्रका है जिसको कि वह इस तकसीम द्वारा अलग करना चाहते हैं।

इस तकसीम बारा अदालत हजा में कई बार फरीकदोम को समन जारी किए जा चुके हैं लेकिन प्यादा की रिपोर्ट से पाया कि उपरोक्त तलवी फरीकदोम नं0 7 ता 9 को साधारण तौर पर नहीं की जा सकती है। क्योंकि उक्त सभी प्रतिवादीगण उपरोक्त पते पर नहीं रहते हैं। इस बारा अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है। अतः आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त तलवी फरीकदोम हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 23 के अन्तर्गत उद्घोषणा की जाकर मुशत्री मुनादी तलव कि जावे। गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 125 बी के अन्तर्गत यह भी उद्घोषणा की जाती है कि जेर अराजी तकसीम खाता खतौनी नं0 19/22,

खसरा नं०, कित्ता-10, रकबा तादादी 14-03-06, बीघा वाक्या मुहाल कनेरी/223 की तकसीम बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज दिनांक 10-09-2024 को प्रातः 11:00 बजे असलातन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें, गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 07-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि०प्र०)

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि०प्र०)

नं० मुकद्दमा : 06/13-B/2024

तारीख दायर : 01-07-2024

श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नी स्व० श्री मुरकी लाल, निवासी गांव बसाहरा, डा० करतोट, तहसील रामपुर,
जिला शिमला, हि० प्र० वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नी स्व० श्री मुरकी लाल, निवासी गांव बसाहरा, डा० करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि० प्र० ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के पति का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र में मुरकी लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल परोग पटवार वृत्त देवठी के कागजात माल में वादिया के पति का नाम तारा चन्द दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादिया महाल परोग के कागजात माल में अपने पति का नाम तारा चन्द के स्थान पर मुरकी लाल दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02-09-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया के पति का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 07/13-B/19

तारीख दायर : 03-07-2024

मदल लाल पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव पटैन, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला,
हि0 प्र0। वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त मदल लाल पुत्र स्व0 श्री मंगत राम, निवासी गांव पटैन, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व पैन कार्ड में मदन लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल कुहल-पटैन के कागजात माल में वादी का नाम मदन सिंह दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल कुहल-पटैन के कागजात माल में अपना नाम मदन सिंह के स्थान पर मदन लाल दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02-09-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 34/13-B/19

तारीख दायर : 05-02-2024

योगिन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव देवठी, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला
शिमला, हि0 प्र0। वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त योगिन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव देवठी, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व पैन कार्ड, राशन कार्ड व शपथ पत्र में योगिन्द्र सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल देवठी व महाल कीम के कागजात माल में वादी का नाम सुकेन्दर सिंह दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल देवठी व कीम के कागजात माल में अपना नाम सुकेन्दर सिंह के स्थान पर योगिन्द्र सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02-09-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 39/13-B/2024

तारीख दायर : 01-03-2024

मोती लाल पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव चिकसा, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला,
हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त मोती लाल पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव चिकसा, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर में मोती लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल कुहल-पटैन के कागजात माल में वादी का नाम मुर्की लाल दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल कुहल-पटैन के कागजात माल में अपना नाम मुर्की लाल के स्थान पर मोती लाल दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02-09-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 40/13-B/18

तारीख दायर : 27-03-2024

रिया चौहान पुत्री स्व0 श्री जीवन सिंह, निवासी गांव जगोट, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त रिया चौहान पुत्री स्व0 श्री जीवन सिंह, निवासी गांव जगोट, डा0 देवठी उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थिया का नाम मुताबिक आधार कार्ड, शपथ पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में रिया चौहान दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल देवठी (पटवार वृत्त देवठी) के कागजात माल में प्रार्थिया का नाम रीमा दर्शाया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थिया महाल देवठी के कागजात माल में अपना नाम रीमा के स्थान पर रिया चौहान दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02-09-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Kumar Verma s/o Khazan Singh, r/o Village Bhankher, P.O. Ahju, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Chuhar Singh Verma instead of Rakesh Kumar Verma. My correct name is Rakesh Kumar Verma. All concerned note it.

RAKESH KUMAR Verma
s/o Khazan Singh,
r/o Village Bhankher, P.O. Ahju,
Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manohar Lal s/o Roshan Lal, r/o VPO Kot Tungal, Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name has been recorded as Manohar Lal in all records instead of Manohar Lal Bhardwaj. I want to enter my surname as Bhardwaj. All concerned please note.

MANOHAR LAL
s/o Roshan Lal,
r/o VPO Kot Tungal,
Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.).

